



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



स. 296]
No. 296]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 17, 1987/ज्येष्ठ 27, 1909
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 1987/JYAISTHA 27, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 17 जून, 1987

अधिसूचना

क्र. आ. 581 (अ):—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्न-
लिखित आदेश मासिक जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

आदेश

भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के उपबंधों और वित्त आयोग
(वित्तीय उपबंध) अधिनियम 1951 (1951 का 33) के उपबंधों
के अनुसरण में, राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करते
हैं, जिसके अध्यक्ष संसद सदस्य श्री एन. के. पी. सार्वे होंगे और
जिसमें निम्नलिखित और अन्य सदस्य सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—

1. स्वामूर्ति श्री अब्दुल्लाह कुरेशी, न्यायाधीश, सर्वस्य
गुजरात उच्च न्यायालय
2. श्री राजा जे जैनेय्या सर्वस्य, योजना आयोग सर्वस्य

3. श्री लालतन आबला, भूतपूर्व मुख्य मंत्री मिजोरम सर्वस्य

4. श्री महेश पण्डित सर्वस्य सचिव

2. आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य उस भारीय से लेकर
जिसकी वे अपना अपना कार्यभार संभालेंगे, 30 जून, 1987 तक पद
धारण करेंगे।

3. आयोग निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिफारिश करेगा:—

(क) कर्गों की उन निचल प्राप्तियों का संघ व राज्यों के बीच
विभाजन, जिनमें संविधान के भाग XII के अध्याय I के
अंतर्गत उनके बीच विभाजित किया जाता है अथवा किया जा
सकता है, तथा ऐसी प्राप्तियों के उनके अपने-अपने भाग का
संयोजन के बीच आवंटन,

(ख) ऐसे निम्नलिखित विषयों के संबंध में से राज्यों
के राजस्व के सहायता-अनुदान अधिवासित होने चाहिए
तथा उन राज्यों की अदा की जाने वाली राशियां जिन्हें
संविधान के अनुच्छेद 275 के खंड (i) के परस्परों में निनि-
विष्ट प्रयोजनों से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए संबिधान के
उसी अनुच्छेद के अंतर्गत उनके राजस्व के सहायता-अनुदानों
के रूप में सहायता की जरूरत हो।

4. अपनी सिफारिश करते समय आयोग निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा—

- (i) राज्यों और केन्द्र के राजस्व खाते की प्राप्ति और खर्चों का मूल्यांकन करने में मानकित दृष्टिकोण अपनाना तथा ऐसा करते समय प्रत्येक राज्य की विशेष समस्याओं, यदि कोई हों और केन्द्र की विशेष आवश्यकताओं जैसे कि रक्षा, सुरक्षा, कृषि की वापसी तथा अन्य प्रतिबद्ध व्यय अथवा देनदारी को ध्यान में रखना,
- (ii) अधिक साधन जुटाने और वित्तीय अनुशासन के लिए पर्याप्त प्रोत्साहनों की व्यवस्था करने की आवश्यकता और साथ ही व्यय तथा राजस्व उपार्जन संबंधी निर्णयों के बीच निकट संयोजन की जरूरत को ध्यान में रखना,
- (iii) सरकारी कामकाज की गति, कार्यकुशलता और प्रभावशालीता की आवश्यकता तथा सरकारी कार्यों की वितरण पद्धतियों को ध्यान में रखना, और
- (iv) न केवल केन्द्र व राज्यों के राजस्व खाते की प्राप्ति और खर्च को संतुलित रखने के उद्देश्य को ध्यान में रखता बल्कि पूँजी निवेश के लिए अधिशेषों का भी निर्माण करना।

5. आयोग, राज्यों में निम्नलिखित साधनों के वितरण को शामिल करने वाले विधायी में, परिवर्तन करने का भी, यदि कोई परिवर्तन संभव हो, सुझाव दे सकेगा—

- (क) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम, 1957 (1957 का 58वाँ) अंतर्गत आरक्षित अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों से किसी एक वित्तीय वर्ष में निवृत्त प्राप्ति, और
- (ख) निर्मित वस्तुओं की बिक्री कर अधिनियम, 1957 (1957 का 25 वा) के अंतर्गत प्राप्त कर के बदले में राज्यों को उपलब्ध किया जाने वाला अनुदान।

6. उपर्युक्त विविध मामलों के संबंध में सिफारिशें करते समय, आयोग ऐसे समस्त मामलों में, जहाँ पर जनसंख्या को करों, शुल्कों तथा सहायता अनुदानों के वितरण के निर्धारण के लिए एक कारक समझा जाए, 1971 की जनसंख्या के आंकड़े अपनाएगा।

7. आयोग, बिक्री कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद-शुल्कों को बुनियादी उत्पाद शुल्कों के साथ विलयित करने की व्यवहार्यता के प्रश्न को जांच कर सकता है और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम 1957 (1957 का 58वाँ) की प्रथम अनुसूची के कालम (3) में अधिग्रहित वस्तुओं के संबंध में आरोप्य उत्पाद-शुल्कों के एक संशोधन को राज्यों में बिक्री कर के बदले प्रावधान करने का एक उपयुक्त सूत्र भी प्रतिपादित कर सकेगा।

8. आयोग, राज्यों के ऋणों की 31 मार्च, 1989 तक की स्थिति का मूल्यांकन करेगा और केन्द्र की वित्तीय अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे उचिततम उपायों का सुझाव देगा, जिन्हें आवश्यक समझा जाए। उचिततम उपायों का सुझाव, आधारभूत परियोजनाओं में किए गए पूँजी निवेश को विशेषरूप से ध्यान में रखते हुए दिया जाएगा और उनका संबंध वित्तीय तथा पंचवर्षीय कार्यकुशलता में सुधार लाने की व्यवस्था में रहेगा।

9. आयोग, देशी वित्तियों से प्राप्त राज्यों के ऋणों किए गए राहत संबंधी व्यय की वित्त-व्यवस्था करने के लिए अपनाई जाने वाली नितियों और किए गए ऋणों का पुनरीक्षण कर सकता है और मौजूदा प्रबंधों में, अन्य बातों के साथ-साथ, किजूल खर्चों से बचने की आवश्यकता की दृष्टि से ऐसे परिवर्तन करने का सुझाव भी देगा, जिन्हें वह जरूरी

समझेगा। आयोग, अन्य बातों के साथ-साथ एक राष्ट्रीय बीमा विधि की स्थापना करने की व्यवहार्यता के प्रश्न को जांच भी कर सकेगा, जिसमें राज्यों की सरकारें अपनी राजस्व प्राप्ति के कुछ प्रतिशतों का अंशदान कर सकेंगी।

10. उपर्युक्त मामलों पर, आयोग दो रिपोर्टें प्रस्तुत करेगा, पहली रिपोर्ट, जो पहली अगस्त 1989 से प्रारंभ होने वाली अवधि से एक वर्ष तक की अवधि के लिए होगी, 30 जून 1988 तक और दूसरी रिपोर्ट जो पहली अगस्त 1990 से प्रारंभ होने वाली अवधि से एक वर्ष तक की अवधि के लिए होगी, 30 जून 1989 तक।

11. आयोग उस आधार का उल्लेख करेगा जिनके अनुसार यह अपने निष्कर्षों पर पहुंचा है और प्राप्ति और खर्चों के राज्यवार अनुमान उपलब्ध कराएगा।

ह/

(जील सिंह)

भारत के राष्ट्रपति

जून 17, 1987

[सं. एक 5(12)-एफ सी जी/86]

के. एस. शास्त्री, अपर सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 17th June, 1987

NOTIFICATION

S.O. 581(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

In pursuance of the provisions of article 280 of the constitution of India, and of the Finance Commission (Miscellaneous Provisions) Act, 1951 (33 of 1951), the President is pleased to constitute a Finance Commission consisting of Shri N.K.P. Salve, Member of Parliament, as the Chairman and the following four other Members, namely :—

1. Shri Justice Abdus Sattar Qureshi, Judge, Gujarat High Court —Member
2. Dr. Raja J. Chelliah, Member, Planning Commission —Member
3. Shri Lalthan Awla, Former Chief Minister of Mizoram —Member
4. Shri Mahesh Prashad —Member Secretary

2. The Chairman and the other Members of the Commission shall hold office from the date on which they respectively assume office upto the 30th day of June, 1989.

3. The Commission shall make recommendations as to the following matters :—

- (a) the distribution between the Union and the States of the net proceeds of taxes which are to be, or may be, divided between them under Chapter I of Part XII of the Constitution and the allocation between the States of the respective shares of such proceeds;

- (b) the principles which should govern the grants-in-aid of the revenues of the States out of the Consolidated Fund of India and the sums to be paid to the States which are in need of assistance by way of grants-in-aid of their revenues under article 275 of the Constitution for purposes other than those specified in the provisos to clause (1) of that article.

4. In making its recommendations, the Commission shall —

- (i) adopt a normative approach in assessing the receipts and expenditures on the revenue account of the States and the Centre and, in doing so, keep in view the special problems of each State, if any, and the special requirements of the Centre such as defence, security, debt servicing and other committed expenditure or liabilities;
- (ii) have due regard to the need for providing adequate incentives for better resource mobilisation and financial discipline as well as closer linking of expenditure and revenue-raising decisions;
- (iii) take into account the need for speed, efficiency and effectiveness of Government functioning and of delivery systems for Government programmes; and
- (iv) keep in view the objective of not only balancing the receipts and expenditure on revenue account of both the States and the Centre, but also generating surpluses for capital investment.

5. The Commission may suggest changes, if any, to be made in the principles governing the distribution among the States of —

- (a) the net proceeds in any financial year of the additional duties of excise leviable under the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), and
- (b) the grants to be made available to the States in lieu of the tax under the repealed Railway Passenger Fares Tax Act, 1957 (25 of 1957).

6. In making its recommendations on the various matters aforesaid, the Commission shall adopt the

population figures of 1971 in all cases where population is regarded as a factor for determination of devolution of taxes and duties and grants-in-aid.

7. The Commission may examine the feasibility of the merger of additional duties of excise in lieu of sales tax with basic duties of excise and evolve a suitable formula for allocating a part of the duties of excise in respect of the goods described in column (3) of the First Schedule to the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957) for distribution among the States, in lieu of sales tax.

8. The Commission may make an assessment of the debt position of the States as on the 31st day of March, 1989 and suggest such corrective measures as deemed necessary keeping in view the financial requirements of the Centre. The corrective measures will be with particular reference to investments made in infrastructure projects and shall have linkage with improvements in financial and managerial efficiency.

9. The Commission may review the policy and arrangements in regard to the financing of relief expenditure by the States affected by natural calamities and suggest such modifications as it considers appropriate, in the existing arrangements, having regard, among other considerations, to the need for avoidance of wasteful expenditure. The Commission may examine, inter-alia, the feasibility of establishing a national insurance fund to which the State Governments may contribute a percentage of their revenue receipts.

10. On the matters aforesaid, the Commission shall make two reports, the first report covering a period of one year commencing on the 1st day of April, 1989, by the 30th June, 1988, and the second report covering a period of five years commencing on the 1st day of April, 1990, by the 30th June, 1989.

11. The Commission shall indicate the basis on which it has arrived at the findings and make available the State-wise estimates of receipts and expenditures.

June 17, 1987

Sd/-

(ZAIL SINGH)

PRESIDENT OF INDIA

[No. F. 5(12)-FCD/86]

K. S. SASTRY, Addl. Secy. (Budget)

